India Media Monitor

Jansatta

Gao mein jabran ek saal bhejne par Doctors ka pradarshan

Date: 09/08/2013 | Edition: Delhi | Page: 4 | Source: Bureau | Clip size (cm): W: 22 H: 15

Clip: 1 of 1

गांवों में जबरन एक साल भेजने पर डाक्टरों का प्रदर्शन

■ बैरिकेड तोड़ा तो आमादा छात्रों पर लाठियां भांजी ■ अनिवार्य की जगह स्वैच्छिक करने की मांग

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 8 अगस्त। एमबीबीएस के छात्रों की एक साल तक अनिवार्य ग्रामीण पोस्टिंग के खिलाफ देश भर से आए मेडिकल छात्रों और डाक्टरों ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आइएमए, डीएमए और सेव दि डाक्टर्स के बैनर तले किया गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की और हल्की लाठी भांजी। धक्का मुक्की में कुछ छात्राओं के पैर में हल्की चोट भी लग गई। बाद में कुछ छात्र पुलिस को चकमा देकर निर्माण भवन स्थित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने भी पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। जिन्हे यहां तैनात पुलिस कर्मियों ने और आगे बढ़ने से रोक दिया।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) ने सेव दि डाक्टर्स अभियान के तहत साथ मिल कर एमबीबीएस के छात्रों की अनिवार्य ग्रामीण नियुक्ति का विरोध किया है। देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का एलान करते हुए छात्रों और डाक्टरों ने मांग की है कि इस नियुक्ति को अनिवार्य बनाने की बजाय स्वैच्छिक तौर पर लाया जाए। अथवा इसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया जाए। ट्रेनिंग के तौर पर इंटर्नशिप को हिस्सा बनाया जाए तो छात्रों को जबरन भेजने की नौबत नहीं होगी, वे स्वेच्छा से जाएंगे।

आइएमए के महासचिव डा. नरेंद्र सैनी ने कहा कि देश भर में परास्नातक स्तर के डाक्टरों के छह महीने के लिए ग्रमीण सेवा में नियुक्ति अनिवार्य करने से समाधान हो सकता है। देश में केवल एमबीबीएस किए छात्रों को नौकरी करने की छूट नही है। वे केवल एमबीबीएस की वजह से स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। साथ ही छात्र की आगे की पढ़ाई भी इससे बाधित होगी। पहले ही डाक्टरों को अपना करियर शुरू करने में करीब सात आठ साल का समय लग जाता है। एक साल की ग्रामीण पोस्टिंग से एक साल या ज्यादा समय और लगेगा।

इतना ही नहीं इसके लिए जरूरी सीटें या संसाधन भी नही है। जरूरी है कि ग्रामीण स्तर पर संसाधन मुहैया कराए जाएं। बड़े डाक्टरों की नियुक्ति हो। उन्हें ऐसी सुविधाएं दी जाएं कि उनके बच्चों का भविष्य दांव पर न लगे। कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाए तो डाक्टर टिकेंगे। पदोन्नति में भी ऐसे डाक्टरों को वरीयता दी जाए जो गांव में सेवाएं देने को तैयार हैं।

डीएमए के अध्यक्ष डा एके अग्रवाल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से चिकित्सा शिक्षा में में संकट बढ़ेगा। आगे स्थिरता भी नही रहेगी। इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन व आइएफएमएसए के छात्रों ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किए गए उपाय किए गए हैं वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। इन्हें सशक्त करने व गावों में डाक्टरों को रोकने के लिए भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जाए। मेडिकल के छात्रों ने गांवों में सेवाएं देने की इच्छा तो जताई है लेकिन पीजी की पढ़ाई के बाद।

डा. सैनी ने कहा कि हर साल देश में करीब 50 हजार छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करके निकलते हैं। पीजी की सीमित सीटें ही हैं। इससे अधिकांश छात्रों के पास पीजी की फिर से तैयारी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। डा. नवनीत मुतरेजा ने कहा कि इनके लिए सीटें बढ़ाने की बजाए सरकार थोपने वाला फैसला लागू कर रही है। सीटें नहीं बढ़ीं तो देश में विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति के बाद विशेषज्ञों की भारी कमी हो जाएगी।

लेकिन इसका स्थाई समाधान करने की बजाए सरकार ग्रामीण सेवा में इन छात्रों को धकेलने की कोशिश कर रही है। बजाए इसके पीजी के छात्रों की छह महीने की ड्यूटी अनिवार्य की जाए। ग्रामीण सेवा में लगे डाक्टरों को पदोन्नति में वरीयता देने, प्रोत्साहन राशि देकर व गांवों में मेडिकल कालेज खोल कर समाधान किया जा सकता है। डा. रोलिका, डा शामन और अन्य छात्रों ने कहा कि अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। पानी के बौछार से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। बैरिकेड तोड़ने पर आमादा छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने हवा में लाठियां भी भांजी।